

LOK SABHA DEBATES

I First day of the Tenth Session of Second Lok Sabha
Vol. XXXVIII]

2 [No. 1

LOK SABHA

Monday, February 8, 1960/Magha 19,
1881 (Saka)

The Lok Sabha met at Thirty-five
minutes past Twelve of the Clock

12.35 hrs.

[Mr. SPEAKER in the Chair]

MEMBER SWORN

Shri D. C. Mallik (Dhanbad)

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I beg to lay on the Table
a copy of the President's Address to
both Houses of Parliament assembled
together on the 8th February, 1960.

President's Address

राष्ट्रपति: संसद् के सदस्यगण,

एक बार फिर संसद् के नये सत्र का भार
संभालने के समय मैं आपका स्वागत करता
हूँ।

२. बीते वर्ष में मेरी सरकार और हमारे
लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र-निर्माण के
काम में संलग्न रहे। देहातों और गहरों में
रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक
उन्नति की आवश्यकताओं और सफलताओं
को अधिकाधिक समझने लगे हैं और इन्हें
अपने दैनिक जीवन के लिये महत्वपूर्ण और
अपनी स्थिति और रहन-सहन के स्तर में
सुधार के लिये आधारभूत मानते हैं।

३. हमारी परम्परागत और सुपरिचित
बीमाओं को लांघ कर, भारतीय गणराज्य
की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के
बुल आने से हमारे लोगों को भारी दुख हुआ

है और उन में ठीक ही व्यापक क्षोभ की
भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों
और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों पर बहुत भार
पड़ा है। हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का
दुख है और अफसोस भी है। हमारे आपसी
सम्बन्धों के निर्धारण के लिये जिन सिद्धांतों
को हमने परस्पर स्वीकार किया था चीन
द्वारा उनकी अवहेलना के कारण ही ये घटनायें
घटी हैं। हमारी सम्पूर्ण सत्ता के लिये पैदा
हुए इन खतरों का मुकाबला करने के हेतु
मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के
क्षेत्रों में सत्वर और सुविचारित कई कदम
उठाये हैं।

४. मेरी सरकार को खास तौर से इस
बात का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी
सामान्य सीमा पर, जहाँ हमारी सेना तैनात
नहीं थी, मैनिंक बल का एक तरफा प्रयोग
किया। यह विश्वासघात है, किन्तु उन
सिद्धान्तों में जिन्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों
के लिये आधारभूत मानते हैं अभी भी हमारी
प्राप्त्या है।

५. संसद् के सदस्यगण, समय समय
पर हमारे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान
मंत्री के बीच पत्रव्यवहार के प्रकाशन द्वारा,
आप को, हमारे दोनों देशों के बीच जो
स्थिति रही है, उस से अवगत रखा गया है।
मेरी सरकार ने यह असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट
कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को
सुलझाने के लिये हम शान्तिपूर्ण प्रयत्न करना
चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता से हमने यह भी
कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुझान
अपनाया है और जो एकतरफा कार्य या निर्णय
किया है, वह हमें मान्य नहीं होगा। इत
लिंबे मेरी सरकार, उचित शर्तों के साथ और

[राष्ट्रपति]

उचित अवसर पर, शांतिपूर्ण बातचीत और इसके साथ ही दृढ़ता से देश के प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है।

६. हम आशा करते हैं कि हमारी कार्यवाही और संसार भर का प्रतिकूल जनमत देर सवेर चीन को इस बात के लिये प्रेरित करेगा कि वह मंथियों और परम्परा द्वारा स्थापित हमारी सामान्य सीमाओं के सम्बन्ध में हम से समझौता करे। केवल इसी प्रकार अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जिनके लिये हमारी सरकार और भारत के लोग आकांक्षी हैं, यथार्थ हो सकत हैं और दोनों देशों के हित में स्थाई बन सकते हैं। यह आशा की जा सकती है, कि जो कार्यवाही हमने की है और जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है, वह चीन को हमारी नीति और दृढ़ता का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगी।

७. संसद् के सदस्यो, हमारी सीमा पर जो स्थिति पैदा हो गई है और उस से जो समस्याएं और परिणाम निकलते हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने कुछ विस्तार से आपसे कहा है। मेरा यह कहना अनावश्यक है कि मैंने जो कुछ भी बताया वह हमारे देश और लोगों की भावनाओं और अपनी सीमाओं की रक्षा के दृढ़ निश्चय को दोहराना मात्र है। किन्तु रक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब उसके पीछे राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता हो। हमारी आर्थिक और औद्योगिक उन्नति, उत्पादन की योजनाओं पर अधिक तेजी और परिश्रम से प्रमल जिससे कि देश को आधुनिक रक्षा के साधन उपलब्ध हो सकें, और इसके साथ ही राष्ट्र में बल और अनुशासन की भावना का मंचार हो सके, ये सब बातें ही देश की सुरक्षा का आधार हैं।

८. चीनी-भारतीय सीमाओं पर घटी घटनायें निःसन्देह दुःखपूर्ण हैं, किन्तु हमें नें देश की उन्नति और आर्थिक व्यवस्था के

योजनाबद्ध विकास के प्रयत्नों को ढीला नहीं करना चाहिये और न हम ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में इन घटनाओं के कारण मेरी सरकार आर्थिक विकास को अधिक गतिमय और व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठा रही है।

९. तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने का काम कुछ और आगे बढ़ा है। इस योजना का क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसके लक्ष्य अधिक ऊंचे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय, १९५०-५१ के मुकाबले में राष्ट्रीय आय को लगभग दो गुना करना और कृषि उत्पादन तथा हमारे खुराक की जरूरतों, भारी मशीनी औजार निर्माण और लोहा, ईंधन तथा बिजली जैसे मौलिक उद्योगों की और अधिक ध्यान देना है। छोटी और ग्रामीण दस्तकारियों का और हमारी देहाती आर्थिक व्यवस्था का स्वस्थ और अविलम्ब विकास और औद्योगिक केन्द्रों तथा देहाती लोगों के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करना, ये बातें उस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

१०. तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे राष्ट्रीय विकास के नाजुक दौर की द्योतक है। इसका ध्येय हमारी आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इस योग्य करना है कि इस से हमारे उत्पादन के साधन बढ़ सकें और उनका आप से विस्तार हो सके। इसके लिए लोगों से निरंतर प्रयास करते रहने और धैर्य रखने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार हमारी तीसरी योजना में इस की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और ग्रामीण चौथी योजना की जरूरतों को सामने रखा गया है। विदेशी सहायता और ऋण के लिये जो हमारे विकास की मौजूदा हालत में जरूरी हैं, हम आभारी हैं, किन्तु अपने ही हित में और अपने अच्छे और उदार मित्रों के हित में और संसार के अद्वैतिकसित क्षेत्रों

की आवश्यकताओं की दृष्टि से, हमें निर्भरता से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए ।

११. देश की विदेशी-मुद्रा-स्थिति अधिक नहीं बिगड़ी और वह प्रायः यथापूर्व है । इसलिए मेरी सरकार व्यापार के लिए ऐसी नीति अपनाना चाहती है जिससे विदेशी मुद्रा की आमदनी अधिक हो और इसके लिये वह आयात पर सख्त नियंत्रण करके निर्यात को बढ़ाने में प्रयत्नशील है । मेरी सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह विदेशी वित्त साधनों को सुरक्षित रख कर हमारे अदृश्य निर्यात की मात्रा को बढ़ावे, जिसके लिये अभी भी बहुत बड़ा, अप्रयुक्त और बढ़ता हुआ क्षेत्र हमारे पास है ।

१२. हमारा औद्योगिक उत्पादन उन्नति की ओर अग्रसर है । वर्ष के प्रथम दस महीनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन १३८ से १४६.३ हुआ है और उत्पादन में दस मात्रा से अधिक की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि सर्वतो-मुखी है जिस में सभी उद्योगों का योगदान है, किन्तु धातु-संबन्धी उद्योगों की उन्नति से उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है । राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों में उत्पादन १६५६ से आरम्भ हो गया है । कच्चे लोहे के उत्पादन में पचास प्रतिशत और इस्पात के उत्पादन में भी काफी, पर इस से कुछ कम, वृद्धि हुई है ।

१३. लोहे और इस्पात के उत्पादन से भारी मशीनों को बनाने की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा । मेरी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले से ही अनेक मशीन बनाने की व अन्य योजनाओं को स्वीकृत किया है । इनमें रांची की भारी मशीन योजना और भिलाई में इस्पात उत्पादन को दोगुना करना, भोपाल की भारी बिजली यंत्र निर्माण योजना का विस्तार, और बिजली, खाद और मशीनी औजार बनाने की कई एक योजनायें शामिल हैं ।

१४. रासायनिक उद्योग ने भी सराहनीय प्रगति की है । रंगाई के साधनों, दवाओं विस्फोटकों और प्लास्टिक के लिये मौलिक कच्चे साधनों की उपलब्धि के लिये एक आरम्भिक मशीन स्थापित की गई है ।

१५. अपने रेल विभाग के प्रयत्नों से हम न केवल इंजनों, रेल के डिब्बों, वेगनों, सिगनल और बत्ती के साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि इनका उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होता है कि निर्यात के लिए भी कुछ सामान बच रहता है ।

१६. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत खान उद्योग भी काफी मात्रा में बढ़े हैं । नयी खोज और अप्रयुक्त क्षेत्र में धातुओं की गहरी खान-बीन के लिये, जो हमारी आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक हैं, भारत के भूगर्भ विज्ञान पर्यवेक्षण का विस्तार हुआ है ।

१७. एक स्थायी तेल और प्राकृतिक गैस कमिशन की भी स्थापना हुई है । देश के विभिन्न स्थानों में तेल की प्राप्ति की ढूँढ खोज जारी है । तेल के उत्पादन के लिये नहारकटिया में साठ तेल-कूप खोदे गये हैं । यह तेल आसाम और बिहार की सरकारी रिफाइनरीज के लिये आवश्यक है । आसाम की रिफाइनरी के निर्माण की प्रगति जारी है ।

१८. बिहार में बरौनी की रिफाइनरी को बनाने के हेतु मशीनों और अन्य साधनों की प्राप्ति के लिये मेरी सरकार ने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के साथ समझौता किया है ।

१९. मेरी सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिये वैज्ञानिकों, तकनीकियों, और टेकनोलोजिस्ट्स की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है । वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि, ऐसे पुराने और नये वैज्ञानिकों के पद ऊँचे करने के लिये, नौकरी की अधिक अच्छी

[राष्ट्रपति]

सुविधायें और सुगमसर देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति के साथ इन क्षेत्रों में नौकरी के सुगमसर नित्य बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक तरीकों पर आधारित हमारे योजना-बद्ध विकास के लिये यह परम आवश्यक है।

२०. हमारे एटमिक विभाग ने बड़ी सराहनीय प्रगति की है। आइसोटोप का अधिक उत्पादन, ईंधन तत्वों का संग्रह, टोम्बे में यूरेनियम मैटल प्लांट, उपयोग में लाये हुए ईंधन से प्लुटोनियम का निकालना और यूरेनियम की खान का संचालन—ये इस विभाग के सफल कार्य रहे हैं। प्रथम न्युक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना का प्रारम्भिक कार्य हाथ में है। यूरेनियम, जो कि बिहार में खोदा जायेगा, इस प्रथम न्युक्लियर पावर स्टेशन को पर्याप्त कच्चा माल दे सकेगा।

२१. एक लाख ग्रास टन के जहाज भारतीय व्यापारी बेड़े में जोड़े गये हैं। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड और एक वैधानिक नानलैसिंग शिपिंग विकास फंड की स्थापना की गई है। भारतीय जहाजरानी को, जिसे स्वाधीनता से पहले बहुत अवरोध सहने पड़े, अब विकास और आधुनिकीकरण के लिये बराबर हर संभव सहायता मिलती रहेगी। मेरी सरकार देश की अर्थ व्यवस्था में व्यापारी बेड़े के महत्व को समझती है। विदेशी मुद्रा के उपार्जन और उसे सुरक्षित रखने के लिये और हमारे लम्बे तट की रक्षा के कार्य में सहायक के रूप में और आवश्यकतानुसार उपयोग के लिये इस बेड़े का बहुत महत्व है।

२२. १९५८ में बनाई गई अनुशासन नियमावली से देश के औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है और उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि तथा औद्योगिक शान्ति बनाये रखने की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५९ में काम के मजदूर दिनों का नुकसान कहीं कम हुआ है।

२३. राजकीय कर्मचारी बीमा योजना का और अधिक विस्तार किया गया है और अब इसके अन्तर्गत साढ़े चौदह लाख कारखानों के मजदूर आते हैं, जब कि योजना के अन्तर्गत दवा दारू की सुविधाओं को मजदूरों के परिवारों तक बढ़ा कर करीब १२ लाख व्यक्तियों पर और लागू कर दिया गया है।

२४. राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का शिक्षण, लड़कियों की शिक्षा का विस्तार और अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति हुई है, और यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के योग्य विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां दी जा रही हैं।

२५. हमारी आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता, विस्तार और दृढ़ता के लिये अनाजों के उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। १९५७-५८ में अनाज का उत्पादन ७ करोड़ ३५ लाख टन हुआ और नकदी फसलों की पैदावार में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई, जिससे कुल मिलाकर कृषि उत्पादन का मूलांक बढ़ कर १३१ हो गया, जो पिछले किसी भी वर्ष की अपेक्षा १४.३ प्रति शत अधिक है। किन्तु देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति से निश्चिन्त तो क्या हम सन्तुष्ट भी नहीं हैं। हर वर्ष हमें खाने के लिये और संचय के लिये भारी मात्रा में अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा के हमारे क्षीण साधनों पर बहुत दबाव पड़ता है और जो हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्रतिकूल है। प्रति एकड़ पीछे हमारा उत्पादन एशिया, यूरोप और अमरीका के बहुत से देशों के उत्पादन की अपेक्षा कम है। मेरी सरकार वैज्ञानिक साधन के उत्पादन और अच्छे बीजों की सप्लाई की तरफ अधिक

ध्यान दे रही है। किन्तु व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्पन्नता के लिये यह आवश्यक है कि भूमि की अच्छी जुताई हो, कीड़ों से फसलों की बर्बादी को रोका जाये, पशु पालन में सुधार हो, खेती और हाट व्यवस्था में सहकारिता को अधिकाधिक स्थान दिया जाये और आत्मभरित होने के लिये लोग दृढ़-संकल्प हों।

२६. देश के आर्थिक विकास में और राष्ट्र के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें, इसके लिये मेरी सरकार ने हमारे महान् और बढ़ते हुए प्रजातंत्र के मौलिक स्तर पर जन-साधारण की संस्थाओं के पक्ष में विकेन्द्रीकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। "पंचायती राज" की यह योजना राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में पहले ही लागू हो चुकी है और दूसरे राज्यों में शुरू होने जा रही है। "पंचायती राज" प्रणाली को कुशल बनाने के लिये सभी श्रेणियों के गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

२७. प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इस दिशा में उत्पादन और उसके साधन दोनों के विस्तार की योजनायें विचाराधीन हैं और उन पर उत्तरोत्तर अमल किया जायेगा।

२८. आगामी वर्ष में मेरी सरकार ने नेशनल कैडेट कोर का विस्तार करने और लड़कियों के लिये नर्सिंग और सहायक टुकड़ियों संगठित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। टैरिटोरियल आर्मी और लोक सहायक सेना की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी और उनकी ट्रेनिंग तथा भावी जिम्मेदारियों में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं।

२९. सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न बलों की सेवा-सम्बन्धी परिस्थितियों में कई एक सुधार किये गये हैं।

३०. भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने और अनुशासित जनशक्ति के इस साधन का उपयोग करने पर सरकार बराबर विचार कर रही है। टेक्नीकल और पेशावर ट्रेनिंग तथा पथप्रदर्शन और सहकारी समितियों द्वारा आत्म-सहायता की योजनाओं का चालू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनः संस्थापन और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आवश्यक अंग है और यह सशस्त्र सेनाओं में काम करने वालों में उचित प्राशा, उत्साह और स्थिरता की भावना का संचार करने का साधन है।

३१. संसद् के सदस्य इस बात से परिचित हैं कि केरल राज्य के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी होने वाली उद्घोषणा में, जिसका अनुमोदन लोक सभा और राज्य सभा ने अपने प्रस्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान सभा के लिये जितनी भी जल्दी सम्भव हो चुनाव किये जायें। तदनुसार साधारण चुनाव हुए और सारे राज्य में एक फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में मत देने वालों की संख्या अभी तक अधिकतम मतदान वाले चुनावों में से रही। शीघ्र ही उद्घोषणा को वापस ले राज्य में साधारण वैधानिक व्यवस्था लागू की जायेगी।

३२. संसद् के पिछले सत्र में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के सदस्यों के लिए लोक-सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में सीटें सुरक्षित रखने सम्बन्धी अभिरक्षण को १० साल तक और बढ़ाने का निश्चय किया गया था, और इस निर्णय से सम्बन्धित संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम के लिये मैं अपनी स्वीकृति दे चुका हूँ। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में जांच के लिये सरकार एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है।

[राष्ट्रपति]

३३. १९५९ में संसद् ने ६३ विधेयक पारित किये। १५ विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

दि ऐटमिक एनर्जी बिल।

दि इंडियन टेलिग्राफ (अमेंडमेंट) बिल।

दि एग्रीकलचरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन बिल।

दि फारवर्ड कांटेक्ट्स (रेग्यूलेशन) एमेंडमेंट बिल।

दि इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाईज बिल।

दि एम्पलाईज प्राविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल।

दि डीक वर्क्स (रेग्यूलेशन अथवा एम्पलाय-मेंट) बिल।

दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) बिल।

दि सैट्रल मेटाली वेनिफिट बिल।

दि इंडियन सेल अथवा गुड्स (अमेंडमेंट) बिल।

दि रिलिज्यूस ट्रस्ट्स बिल।

दि टू-मेम्बर कांस्टिट्यूटोर्स (अबोलीशन) बिल।

और, दि पेमेंट अथवा वेजेस (अमेंडमेंट) बिल।

३४. मीजूदा बम्बई राज्य के पुनर्गठन और दो अलग राज्यों के संस्थापन के लिये मेरी सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

३५. वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर मेरी सरकार अपना निर्णय पहले ही घोषित कर चुकी है। दूसरी सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। जगन्नाथदास आयोग जांच के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेन्शन आदि में वृद्धि के वारण, अनुमान है, करीब ३१ करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय बैठेगा।

३६. १९६०-६१ वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

३७. संसार में तनाव की भावना में ढिलाई और निःशस्त्रीकरण और शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच उच्च स्तर के सम्मेलनों की संभावनाओं पर मेरी सरकार सन्तोष प्रगट करती है। महान राजनीतिज्ञों, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ की मन्त्री परिषद के अध्यक्ष, हमारे देश और देशवासियों की प्रशंसा और सद्भावना के अधिकारी हैं। स्वेच्छा से अपने-अपने देश में न्यूक्लीयर विस्फोटों के स्थगन को जारी रखने और इन समस्याओं को सुलझाने के लिये अमेरिका और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रयत्नों का मेरी सरकार स्वागत करती है, पर इस विचार को फिर से दोहराती है कि जन-विध्वंस के अस्त्रों का परीक्षण बन्द होना चाहिये।

३८. बड़े राष्ट्रों के नेताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क और इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत करते हैं और इन प्रयासों की सफलता चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयास विश्व शान्ति के लिये और शस्त्रास्त्रों के संचय की दौड़ को रोकने की सच्ची इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

३९. शस्त्रास्त्रों की भयानक उत्पत्ति और उनसे पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय और द्वेषों के बीच मेरी सरकार दिल से ऐसे युद्धहीन विश्व की कल्पना जागृत करने वाली नई घटनाओं का स्वागत करती है जिनमें राष्ट्र हथियारों को ही नहीं त्याग देंगे बल्कि आपसी झगड़ों के निपटारे के लिये युद्ध का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शक्तियों और साधनों को शान्ति पूर्ण विश्व के निर्माण में लगा देंगे।

४०. हमारी सरकार और लोग संसार में शान्ति और सहयोग बनाये रखने के लिये

तत्पर हैं। वे शान्तिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और दृष्टिकोण, हमारा विश्वास और व्यवहार और हमारे लोगों की उत्कट इच्छायें तथा धारणायें हैं, स्थिर रहने के लिये दृढ़-संकल्प हैं। इस नीति का संसद् ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है।

४१. मुझे कम्बोडिया, वियेतनाम गणराज्य, वियेतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य, लाओस और श्रीलंका की यात्रा करने का सौभाग्य मिला और इन देशों की सरकारों तथा लोगों द्वारा सुखद और उदार स्वागत का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ।

४२. मुझे अपने देश की राजधानी में अमेरिका के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति का स्वागत करने का हर्ष हुआ। ये दोनों महानुभाव अपने व्यक्तित्व में अपने देशों की शक्ति और महानताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि विद्व शान्ति के लिए अपने देशवासियों की प्रबल इच्छाओं के प्रतिबिम्ब हैं। सोवियत संघ की मंत्री परिषद् के अध्यक्ष, श्री खुश्चेव के आगमन की, जो संसार में एक और शान्ति दूत हैं, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण और शान्ति की खोज में इन दोनों महान देशों और दूसरों के भी प्रयत्नों के पीछे हमारी पूर्ण सद्भावना और नैतिक समर्थन होगा।

४३. मेरी सरकार को अफ़गानिस्तान, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, घाना, नेपाल और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत कर खुशी हुई। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, महामहिम मुरक्को मन्नाट और फिनलैंड के प्रधान मंत्री की हम उत्सुकता से राह देख रहे हैं।

४४. हमारे उप-राष्ट्रपति ने फिलिपीन्स, नारवे, डेन्मार्क और फिनलैंड की यात्रा की और इन सभी जगहों की सरकारों और लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

४५. हमारे प्रधान मंत्री ने अफ़गानिस्तान, ईरान और नेपाल की यात्रा की और वहां उनका सद्भावना से श्रोतप्रोत स्वागत हुआ।

४६. भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों की एक दूसरे के यहां यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री और निकटता की भावना को और दृढ़ता मिली और दोनों देशों के हित में सहयोग का निश्चय हुआ और उसके लिए प्रबल इच्छा प्रकट हुई।

४७. राष्ट्रमंडल के देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को कई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में हमारे भाग लेने के कारण बढ़ावा मिला और हमारी आन्तरिक और विदेश नीतियों तथा हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति अधिक सद्भावना पैदा हुई।

४८. मुझे खुशी है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों पर समझौता हो गया है। मेरी सरकार को आशा है कि पाकिस्तान के साथ इस समझौते के फलस्वरूप हमारे पड़ोसी के साथ, जिससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की हमारी हमेशा इच्छा रही है, सीमा निर्धारण का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा।

४९. भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक मामलों को सुलझाने की दिशा में भी प्रगति हुई है और यह आशा है कि नहरों के पानी सम्बन्धी पुराना झगड़ा भी शीघ्र ही तय हो जायेगा। इन घटनाओं का, जिनसे हमें पूर्ण आशा है कि दोनों देश एक दूसरे के निकट आयेगे, मैं स्वागत करता हूँ।

५०. गत २५ सितम्बर, १९५६ को स्वर्गीय एस० डब्ल० आर० डी० भंडारनायक, श्रीलंका के प्रधान मंत्री, की हत्या के समाचार से भारत के लोगों और सरकार को बहुत दुःख हुआ और चोट पहुँची। वे भारत के बड़े मित्र थे और हमारे देश में कई बार आये थे। श्रीमती भंडारनायक, उनके बच्चों और

[राष्ट्रपति]

श्रीलंका के लोगों और सरकार के प्रति हमने हार्दिक समवेदना प्रकट की।

५१. संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उपनिवेश देशों की आजादी की समस्या, विशेषकर अल्जीरिया के लोगों के निरंतर स्वातंत्र्य युद्ध के प्रति, हमारे देश के लोगों की सहानुभूतिपूर्ण भावना प्रकट की।

५२. केमरून की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, स्वाधीनता का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में अफ्रीका के कई और उपनिवेश देश इसी प्रकार राष्ट्र पद प्राप्त कर लेंगे।

५३. दक्षिण अफ्रीकी संघ की सरकार की जाति के आधार पर पृथकता की नीति के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को जो उस देश के नागरिक हैं अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ रहे हैं। इन लोगों में बहुत से मूल भारतीय भी शामिल हैं। यह नीति संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है और संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के पिछले सत्र में इस नीति की फिर से घोर निन्दा की गई।

५४. मेरी सरकार ने दक्षिण अमेरिका में क्यूबा, वेनज्वेला और कोलम्बिया से तथा अफ्रीका में गिनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है।

५५. संसद् के सदस्यगण, मैंने आपके सामने गत वर्ष की प्रमुख घटनायें, सफलतायें और चिन्तायें रखी हैं। मैंने आपको उन सब महान कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन कराया जो इस समय हमारे सामने हैं। ये सब आपके गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा करती हैं। हमारे आर्थिक आयोजन, देश की प्रतिरक्षा और विश्व शान्ति

में हमारे योगदान के लिए, देश की सरकार और लोगों को अधिकाधिक आपकी सूझ-बूझ तथा सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार संसद् संविधान के द्वारा इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी।

५६. हमने इस वर्ष अपने नन्हें गणराज्य की दसवीं वर्ष गांठ मनायी। हमारा संविधान, जो हमने अपने लिये निश्चित किया और जिसके अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित है और जनता से ही प्रवाहित होती है, स्थिर रहा और उसमें शक्ति का संचार हुआ। मेरी सरकार और हमारे लोगों की नीतियों तथा सफलताओं से हमारे प्रजातन्त्र को बल मिला और उसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है।

५७. हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा स्वातंत्र्य युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार विकसित हुआ कि अपने राष्ट्रपिता के जीवन और उदाहरण से हमें प्रेरणा मिली। अपने नन्हें गणराज्य के इस ११वें वर्ष में हम अपने अतीत और भविष्य को गर्व और विश्वास के साथ, किन्तु अत्यधिक निश्चिन्तता के साथ नहीं, देख सकते हैं। हमारे सामने जो कार्य हैं, वे विशाल हैं। उन्हें सम्पन्न करने के लिये अपने लोगों और देश के प्रशासन में निरन्तर सतर्कता, अधिकाधिक दृढ़ता, अनुशासन और उद्देश्य की भावना की जरूरत है। इस प्रकार ही देश के जन गण के लिये हमारा प्रजातन्त्र यथार्थ और सच्चा हो सकता है।

५८. हमारे विस्तृत साधन और हमारे लोगों की योग्यतायें, निर्माण और उन्नति के उस महान कार्य में लगी हैं, जो हमारे सामने हैं। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक और विचारणीय है कि हमारे प्रशासन की योग्यता भी उसी कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना लाई जाये,

कार्य-प्रणाली को सरल और सुबोध बनाया जाय और उसे इस प्रकार चलाया जाय कि उसमें सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाय और जनशक्ति तथा समय का अपव्यय न हो ।

५६. मेरी सरकार का यह बराबर यत्न रहेगा कि नीतियों के निर्माण और उनको कार्यान्वित होने में जो समय लगता है वह कम से कम हो, सभी वर्गों और आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों के लोग हमारी योजनाओं में भाग ले सकें और इस प्रकार योगदान दे कर वे आत्मोपयोगी और गर्व की भावना का अनुभव कर सकें जो हमें स्वतन्त्रता में मिली है ।

६०. मेरी सरकार मातृभूमि की स्वाधीनता और हमारे लोगों की गरिमा को बनाये रखने, एकता की भावना को प्रोत्साहित करने, सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने और ऐसे प्रजातन्त्रात्मक समाजवादी समाज का गठन करने के लिये, जिसमें उन्नति लोगों की सहमति और शान्तिपूर्ण ढंग से ही प्राप्त की जाय, संगठित करने के लिये कृतमंकल्प है ।

६१. संसद् के सदस्यगण, अब मैं आपके नये सत्र का काम आपको सौंपता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ । मेरी यह सत्याकांक्षा है कि बुद्धिमानी, सहिष्णुता और सहयोग की भावना आपके प्रयत्नों का मार्ग दर्शन करें । आपके प्रयत्न, देश के और देशवासियों के तथा समस्त विश्व के, जिसकी सेवा करना हमारे लिये गौरव का विषय है, हित में सफल हों, यही मेरी प्रार्थना है ।

The President: Members of Parliament, once again, it is my privilege to welcome you to your labours in a new session of Parliament.

2. In the year we leave behind, my Government and our people had been engaged, more than ever before, in

their endeavours in nation-building. The needs and achievements in economic and social advance are understood by our people, in town and village, in increasing measure, as basic and vital to the improvement of their conditions and standards of living and as important to their daily lives.

3. The incursions into parts of the territory of the Union of India, across our traditional and well understood borders, by elements of Chinese forces have, however, deeply distressed our people and evoked legitimate and widespread resentment. They impose a greater strain on our resources and our nation-building endeavours. We regret and deplore these developments on our border. They have resulted from the disregard by China of the application of the principles, which it had been mutually agreed between us, should govern our relations. My Government have taken prompt and calculated measures, both defensive and diplomatic, to meet the threat to our sovereignty.

4. My Government particularly deplore the unilateral use of force by our neighbour on our common frontier, where no military units of the Union were functioning. This is a breach of faith; but we may not lose faith in the principles which we regard as basic in the relations between nations.

5. Members of Parliament: You have been kept informed by the release, from time to time, of the correspondence between my Prime Minister and the Prime Minister of China, of the respective positions of our two countries in this matter. My Government have made it clear, beyond doubt, that they seek a peaceful approach in the settlement of outstanding matters. They have also stated and reiterated, equally clearly, that they will not accept the course, or the results of unilateral action or decisions, taken by China. My Government, therefore, pursues a policy both of a peaceful approach, by negotiation under appropriate conditions, and of being determined and ready to defend our country.

[The President]

8. This and the weight of world public opinion which is adverse to her action should, we hope, persuade China sooner than later to come to agreements in regard to our common frontiers which for long have been well established by treaties, custom and usage. Thus, and thus alone, can friendly relations with our great neighbour which my Government and our people desire, become a reality and endure for our common good. The actions taken and the policy pursued by my Government, it may be hoped, will be adequate to convince China of both our policy and our determination.

7. Members of Parliament: I have referred at some length to the situation that has developed on our border and to the consequences and problems thereof. I need hardly say that in doing so I have reiterated the sentiments of our entire country and our people and their determination to defend our territory. Defence, however, is effective only with national unity and strength. Our economic and industrial advance, the gearing of our production and our plans to greater endeavour and larger and speedier results, which will enable the country to make available to itself the means and the resources for modern defence and, at the same time, help the nation to become strong and disciplined, can alone render her secure.

8. Distressing as these Sino-Indian border developments have been, we may not, and we do not, relax our efforts for the planned development of our economy and our country. In point of fact, because of this situation, my Government are taking steps to speed up further, organise and streamline our economic development.

9. The work on the preparation of the frame and the outline of the Third Five Year Plan with its longer perspective and higher targets is making good progress. The objective of the Third Five Year Plan is to seek almost to double the national income, taking 1950-51 as the basic level, and to pay

much greater attention to agricultural production and to our food requirements, to heavy machine building and to the development of basic resources such as steel, fuel and power. Small-scale and rural industries, the speedier and healthy development of our rural economy, and the healthy relationship between rural areas and industrial centres are among the main aims of the Plan.

10. The Third Five Year Plan represents a critical period in our national development. It aims at making our economy more self-reliant and capable of increasing and generating resources for its further and larger development. It calls for sustained efforts and endurance of our people. Thus, our Third Plan will keep well in view, both its own developmental aspects as well as the requirements and the perspective of the Fourth Plan to follow. While we are grateful for external aid and loans, as necessary in the present stage of our development, we should, in our own interests, in consideration of those who have been our good and generous friends, and the needs of the underdeveloped areas of the world strive to shed our dependence.

11. The country's foreign exchange position while it shows no deterioration, remains more or less unchanged. My Government, therefore, pursue a policy to create a more favourable balance of trade and to earn more foreign exchange by strict control over imports and efforts to increase exports. It will be the endeavour of my Government to conserve our foreign resources and add to the volume of our invisible exports in which there still exists unutilised a vast and increasing field.

12. Our industrial production shows a pronounced upward trend, and for the first ten months of the year, an increase of over ten points has been recorded, from 138 to 149.3, over the last year's figures. This is an all-

round increase to which all industries have contributed, but special mention may be made of the rise in the output of metallurgical industries. The three steel plants at Rourkela, Bhilai and Durgapur have gone into production in 1959. There has been a fifty per cent. increase in the production of pig iron and a somewhat lower, though considerable, increase in the output of steel.

13. The iron and steel output would help to advance the Heavy Machine building projects. My Government have already sanctioned a number of machine building and other projects for the Third Five Year Plan. These include the doubling of the Heavy Machinery Project at Ranchi and the steel production at Bhilai, the expansion of the Heavy Electrical Project at Bhopal, a number of new projects for power, fertiliser plants and Heavy Machine Tools.

14. The Chemical Industry has also witnessed appreciable advance. An Intermediates Plant to provide the basic raw materials for the manufacture of dye stuffs, drugs, explosives and plastics is being established.

15. The endeavours of our Railway organisation to attain self-sufficiency in regard to essential equipment have enabled it not only to meet all the requirements of steam locomotives, coaches, wagons, signalling and lighting equipment, but also to yield a surplus for export.

16. Mining activities in the public sector have increased considerably. The Geological Survey of India has been expanded to undertake search and intensive investigation in virgin areas in minerals essential to our expanding economy.

17. A Statutory Oil and Natural Gas Commission has been established. The search for and discovery of oil in different parts of the country continues. Sixty oil wells have been drilled in Nahorkatiya for the production of crude oil required for the two

State-owned Refineries in Assam and Bihar and the construction of the Refinery in Assam is in progress.

18. My Government have entered into an agreement with the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the supply of equipment for the construction of the Refinery at Barauni in Bihar.

19. My Government are alive to the requirement of scientists, technicians and technologists for our expanding economy. Measures are being taken to step up progressively the output in these cadres and to provide increasingly better career opportunities and a higher status for the old and new entrants. In our developing economy, there are ever growing opportunities of service in these fields, which are so important to our planned development on modern lines.

20. Our Atomic Energy organisation has recorded commendable progress. Increased production of isotopes, the fabrication of fuel elements, the Uranium Metal Plant at Trombay, the extraction of Plutonium from the used fuel elements and the mining of Uranium are among the achievements of this organisation. The preliminary work for the setting up of the first Nuclear Power Station is well in hand. The Uranium which is sought to be mined in Bihar will supply sufficient raw material to feed the first Nuclear Power Station.

21. An additional tonnage, of one lakh gross, was added to the Indian Merchant Fleet. A National Shipping Board and a statutory non-lapsing Shipping Development Fund have been established. Indian shipping, which has suffered many handicaps in the pre-Independence period, will continue to receive all possible assistance in its modernisation and development. My Government is fully aware of the place of the Merchant Navy in our economy, in the conservation and earning of foreign exchange and in its auxiliary and reserve roles in the defence of our long sea coast.

[The President]

22. The Code of Discipline evolved in 1958 has improved the climate of industrial relations in the country and created more favourable conditions for the maintenance of industrial peace and increase of efficiency. Compared to the previous year, there has been an appreciable reduction in the loss of man days of work in 1959.

23. The Employees State Insurance Scheme has been extended to further areas and now covers about fourteen and a half lakhs of factory workers, while medical care under the Scheme has been extended to about twelve lakhs of members of the workers' families.

24. In the field of National Education, the teaching of science subjects, expansion of girls' education and the training of women teachers have made good progress and are gathering momentum. All eligible college students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are receiving stipends.

25. Advance in the production of food is vital to the sustenance, expansion and strength of our economy. Foodgrains production attained a record level of 73.5 million tons and cash crops also recorded satisfactory yields resulting in the overall increase in the Index of Agricultural Production to 131.0, an increase of 14.3 per cent. over the previous record in 1957-58. We cannot, however, feel satisfied, much less complacent, about the food production in our country. Each year, we are obliged to import considerable quantities of foodgrains for consumption and for reserve stocks, causing great stress on our slender foreign exchange resources and rendering our economy far from self-reliant. Our production per acre falls short of the yields in many of the countries of Asia, Europe or America. My Government are giving greater attention to the increased production of fertilisers and to the supply of good seeds. It is, however, by better cultivation, avoidance of waste through pests, better animal husbandry, the advance of co-operation both in production

and in marketing, and by the determination of the people to be self-reliant, that individual and national prosperity can be achieved.

26. To enable greater participation in the conduct of affairs and the development of our economy by the people of the country as a whole, my Government have encouraged schemes of devolution of authority to statutory institutions of the people at the basic level of our great and growing democracy. This scheme of "Panchayati Raj" has already been inaugurated in Rajasthan and in Andhra Pradesh and is making progress in other States. To make the working of the "Panchayati Raj" efficient, a comprehensive programme of training non-officials of all categories has been undertaken.

27. Defence production has made satisfactory progress. Plans of expansion in this field, both of production and of capacity, are under consideration and will be progressively implemented.

28. My Government have taken steps to expand the National Cadet Corps in the coming year and to form units of nursing and auxiliary services for girls. The Territorial Army and the Lok Sahayak Sena will also be expanded in numbers, and certain changes introduced in regard to their training and reserve liabilities.

29. A number of measures for the improvement of the conditions of service in the various categories in the Armed Forces have been implemented.

30. The re-settlement of ex-servicemen and the utilisation of the reservoir of disciplined manpower that they provide are continually engaging the attention of my Government. Schemes of technical and vocational training and guidance and of self-help by co-operatives are promoted. Welfare and re-settlement of ex-servicemen are integral to defence considerations and provide a necessary incentive and a

legitimate measure of hope and security for those who serve the Armed Forces.

31. Members of Parliament are aware that in the Proclamation issued in relation to the State of Kerala on the 31st of July, 1959, which was approved by Resolutions passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha, it was provided that the general election for constituting a new Legislative Assembly for that State shall be held as soon as possible. The general election was accordingly held and polling took place in the entire State on February 1, the number of voters exercising their franchise being one of the highest recorded in any election. The Proclamation will be revoked and the normal constitutional machinery restored in the State shortly.

32. Parliament decided during the last session to extend the safeguards provided in the Constitution for the reservation of seats for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and the State Legislatures by a further period of ten years and the Constitution (Eighth Amendment) Act embodying this decision has received my assent. Government also propose to appoint a Commission as required under Article 339 of the Constitution to examine and report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States.

33. Sixty-three Bills were passed by Parliament in 1959. Fifteen Bills are pending before you. My Government intend to introduce a number of legislative proposals both by way of Bills and amendments. Such proposals will include:—

The Atomic Energy Bill;

The Indian Telegraph (Amendment) Bill;

The Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Bill;

The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill;

The Indian Patents and Designs Bill;

The Employees' Provident Fund (Amendment) Bill;

The Dock Workers (Regulation of Employment) Bill;

The Plantation Labour (Amendment) Bill;

The Central Maternity Benefit Bill;

The Indian Sale of Goods (Amendment) Bill;

The Religious Trusts Bill;

The Two-Member Constituencies (Abolition) Bill; and

The Payment of Wages (Amendment) Bill.

34. My Government also propose to introduce a Bill for the reorganisation of the present Bombay State and to reconstitute it as two separate States.

35. My Government have already announced their decisions on the major recommendations of the Pay Commission. The other recommendations are under their active consideration. The additional commitments on account of the pay, allowances and pensionary charges alone are estimated to be about thirty-one crores per annum, in respect of the Services directly covered by the Jagannadha Das Commission Enquiry.

36. A statement of the estimated Receipts and Expenditure of the Government of India for the financial year 1960-61 will be laid before you.

37. My Government note with gratification the relaxation in world tensions and the prospect of high level meetings of the Heads of Governments for the promotion of World Disarmament and Peace. The initiative of great statesmen, notably the President of the United States of America and the Chairman of the Council of Minis-

[The President]

ters of the Soviet Union, deserve the attention and appreciation of our country and people. My Government, while welcoming the continuance of the voluntary unilateral suspension of nuclear test explosions and the increasing endeavours of both the United States of America and the Soviet Union to solve this problem, reiterate their view that the testing of weapons of mass destruction should be abandoned.

38. We welcome these trends and the direct contacts between the leaders of the Great Powers and wish success to their efforts, which we feel assured are inspired with sincere desire to halt the armaments race and for world peace.

39. We also welcome wholeheartedly, in the midst of the awesome growth of armaments and the fear and passions from which they spring are on which they rest, the newer development of the projection of the picture of a warless world, wherein nations will not only lay down their arms, but reject war as a method of settling disputes and devote their energies and resources to building a peaceful world.

40. Devoted as my Government and people are to world peace and co-operation, they are determined to adhere to a peaceful approach and the policy of Non-alignment, to both of which our country stands fully committed by history and outlook, faith and conduct, and by the overwhelming desires and convictions of our people. Parliament has expressly endorsed this policy on several occasions.

41. I have had the privilege and pleasure of visiting Cambodia, the Republic of Vietnam, the Democratic Republic of Vietnam, Laos and Ceylon, and to receive the generous welcome and joyous greetings of their Governments and peoples.

42. I was happy to welcome to our Capital the President of the United

States of America, and later the President of the Soviet Union, who in their persons represent not only the greatness and power of their countries, but also the fervent desires of their peoples for world peace. We are looking forward to the visit of the Chairman of the Council of Ministers of the Soviet Union, Mr. Khrushchev, another messenger of peace in the world today. The goodwill and moral support of this country will be behind the efforts of these two great countries, and those of others, in full measure in their search for Disarmament and Peace.

43. My Government were glad to welcome the Prime Ministers of Afghanistan, Australia, Cambodia, Ghana, Nepal and Sweden. We look forward to the visits of President Nasser of the United Arab Republic, His Majesty the King of Morocco and the Prime Minister of Finland.

44. The Vice-President visited the Philippines, Norway, Sweden, Denmark and Finland, receiving cordial welcome from the Governments and the people there.

45. My Prime Minister visited Afghanistan, Iran and Nepal, and was welcomed with an abundance of goodwill.

46. The exchange of visits of my Prime Minister and the Prime Minister of Nepal has further strengthened the bonds of affinity and friendship and proclaimed the desire and determination for co-operation in the interests of our two countries.

47. Our relations with Commonwealth countries and our participation at various Commonwealth gatherings have served to create greater understanding of our internal and external policies and, in an appreciable measure, served also to assist our economic development.

48. I am happy to note that further agreements have been reached with

Pakistan in regard to our boundary disputes. It is the hope of my Government that these arrangements with Pakistan will lead to a successful delimitation of our boundaries along our frontiers with our neighbour with whom we have always desired to remain in friendly relations.

49. Progress have also been made in regard to the settlement of financial issues pending between India and Pakistan, and it is hoped that the long-standing Canal Waters dispute will be settled soon. I welcome these developments which bring promise of closer relations between our two countries.

50. The Government and the people of India were deeply grieved and shocked to learn of the assassination of the Prime Minister of Ceylon, the late S. W. R. D. Bandaranaike, on September 25, 1959. He was a great friend of India and visited us several times. Our heartfelt sympathies went out to the Government and people of Ceylon, as well as to Mrs. Bandaranaike and her children.

51. In the United Nations, our delegation reflected the deep feelings of our people in regard to the problem of the liberation of colonial countries and, more particularly, in regard to Algeria, in the sustained struggle of the Algerian people for their national independence.

52. We welcome the independence of the Camerouns, till recently under French administration. We look forward to the emergence to nationhood in the coming years of several other colonial areas in Africa.

53. The policy of apartheid, pursued by the Government of the Union of South Africa, inflicts untold suffering and indignity on the majority of the people who are subjects of that Government. These include large numbers of people of Indian origin. This policy constitutes a violation of Human Rights under the Charter of the United Nations, and it has again met with

overwhelming disapproval by the United Nations in the last session of the General Assembly.

54. My Government have decided to exchange diplomatic representatives with Cuba, Venezuela and Colombia in South America and Guinea in Africa.

55. Members of Parliament: I have placed before you the main events and achievements and our concerns of the past year. I have also projected before you some of the great tasks and burdens that are in front of us. They must engage your dedicated attention. Your understanding and co-operation, in regard to problems of our economic planning, the defence of our country and our contribution to world peace, are required by our Government and people in increasing measure. Thus will Parliament fulfil its historic role in our Constitution.

56. We have celebrated this year the tenth anniversary of our young Republic. Our Constitution which we gave unto ourselves, wherein all power and authority are based upon and spring from the people, has endured and grown in strength. The policies and achievements of my Government and of our people have strengthened our democracy and continue to import into it economic and social content in increasing measure.

57. We are fortunate in the historic background that our national struggle developed and the inspiration that the life and example of the Father of the Nation gave to us. In this eleventh year of our young Republic, we may look back as well as forward, with pride and confidence, though not with complacency. The tasks ahead of us are stupendous. They call for constant vigilance, greater determination and discipline and a sense of purpose both among our people and in our administration. This alone will make our democracy a reality in terms of the masses of our people.

[The President]

58. Our vast resources and the qualities of our people have become engaged in the tremendous tasks of construction and progress that lie ahead of us. In these, the quality of our administration into which must be imported an ever-increasing sense of urgency, rationalisation of procedures, the emergence and development of greater confidence at all levels, and the avoidance of waste of manpower and time, must be an urgent consideration.

59. It will continue to be the constant endeavour of my Government to initiate and further, efforts and plans to bridge the gaps between the time of formulation of policies and their implementation, to enable our people to participate at all levels in our economic and social developments, and for them to feel a sense of function and dignity which Independence has brought to us.

60. My Government seeks to uphold the dignity and independence of our land and people, to promote our unity and social well-being, and to build a democratic and socialist society in which progress is sought and attained by peaceful means and by consent.

61. Members of Parliament: I bid you to your labours in this new session and wish you all success. I earnestly trust that wisdom and tolerance and a spirit of co-operative endeavour will guide you. May your labours bear fruit for the good of our country and people and the world whom we are all privileged to serve.

PAPER LAID ON THE TABLE

PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

Secretary: I beg to lay on the Table a copy of the "Parliamentary Committees—Summary of Works", pertaining to the Ninth Session of the Second Lok Sabha.

DOWRY PROHIBITION BILL

AS RETURNED BY RAJYA SABHA WITH AMENDMENTS

Secretary: Sir, I lay on the Table of the House the Dowry Prohibition Bill, 1959 which has been returned by Rajya Sabha with amendments.

12.37 hrs.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following five Bills passed by the Houses of Parliament during the last Session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 21st December, 1959:—

- (1) The Appropriation (No. 8) Bill, 1959.
- (2) The Sugar (Special Excise Duty) Bill, 1959.
- (3) The Mineral Oils (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Bill, 1959.
- (4) The Indian Tariff (Amendment) Bill, 1959.
- (5) The Married Women's Property (Extension) Bill, 1959.

Sir, I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary of Rajya Sabha, of the following nine Bills passed by the Houses of Parliament during the last Session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 21st December, 1959:—

- (1) The Securities Contracts (Regulation) Amendment Bill, 1959.
- (2) The Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1959.
- (3) The Haj Committee Bill, 1959.
- (4) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1959.
- (5) The Arms Bill, 1959.